

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 10/25

GCMS NO 2025/14

नाथ्या उर्फ नाथूलाल पुत्र दुर्गा जाति मीना निवासी ग्राम पूनेता तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. काबूलाल पिता कल्याण

2. कालूलाल पिता कल्याण जातियान मीना निवासीयान चौकीदार मोहल्ला गंगापुर सिटी
3. नारंगी देवी पुत्री कल्याण जाति मीना निवासी चौकीदार मोहल्ला गंगापुर सिटी
4. तोफी देवी पुत्री कल्याण जाति मीना निवासी चौकीदार मोहल्ला गंगापुर सिटी
5. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर

रेसपो

(अपील विरुद्ध मु0नं0 86/22 निर्णय दिनांक 23.12.24 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री राजेश कुमार मीना  
अभिभाषक रेसपो श्री इंसाफ अली

दिनांक 19.6.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.12.24 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली पेश की है।  
अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख0न0 1250 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा, 1251 रकबा 11 विस्वा, 1260 रकबा 12 विस्वा वाके ग्राम पूनेता तहसील बौली पर पूर्व मे वादी के पिता दुर्गा एवं दूर्गा से पूर्व उनके पिता का कब्जा काशत रहा है। वादी के पिता दुर्गा के फौत होने के पश्चात वादी का लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काशत चला आ रहा है। उक्त भूमि की खातेदारी गलत से कल्याण पुत्र जुवारया मीना निवासी पूनेता के नाम लग गई थी। जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति काफी वर्षों से ग्राम पूनेता मे नहीं है एवं न ही उसका इस भूमि पर कभी कब्जा रहा है। हाल सेटलमेंट मे साबिक ख0न0 1250 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा, 1251 रकबा 11 विस्वा, 1260 रकबा 12 विस्वा के नये खसरा न0 1506 रकबा 0.03 है0, 1515 रकबा 1.47 है0 1517 रकबा 0.02 है0, 1519 रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.58 है0 बने है। साबिक ख0न0 1250 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम पूनेता की खातेदारी गलत रूप से कल्याण पुत्र जुवारया के नाम दर्ज हो गई जबकि कल्याण पुत्र जुवारया का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काशत नहीं रहा है। बल्कि हाल ख0न0 1506 रकबा 0.03 है0, 1515 रकबा 1.47 है0 1517 रकबा 0.02 है0, 1519 रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.58 है0 पर कब्जा वादी के बुजुर्गों के समय से ही चला आ रहा है। इस प्रकार वादी का पुराना कब्जा होने के आधार पर उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी कल्याण पुत्र जुवारया के स्थान पर अपने नाम




राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

खातेदारी लगवाने का अधिकारी है। इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रार्थी का काफी लम्बा समय से कब्जा चला आ रहा है। सेटलमेंट की गलती के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। जिसके लिए उनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक है एवं उक्त भूमि की वर्तमान खातेदारी से कल्याण पुत्र जुबारया का नाम हजफ कर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वह उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपनी सामान्य दिनचर्या में पारित किया है। जो निरस्त योग्य है तथा निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट के हितों को दरकिनार करते हुए अपनी मनमर्जी का निर्णय पारित किया है। इसका प्रमाण अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.12.24 को अस्वीकार करके खारिज किया है ना कि खारिज क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात को दबे मन से माना कि रेस्पों ग्राम पूनेता के मूल निवासी व स्थाई निवासी नहीं है और उनके पिता कल्याण पुत्र जुबारया मीना के नाम वादग्रस्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से या रेस्पों के पिता के प्रभाव में आकर जमाबंदी में दर्ज हो गई है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। रेस्पों ने मात्र यह अपने जबाब में यह कहकर इतिश्री कर ली कि उक्त भूमि उनके पिता कल्याण मीना के नाम पर आवंटित हुई थी जबकि यह सरासर गलत है। क्योंकि रेस्पों ने अपने पिता के नाम पर भूमि आवंटन आदेश दिनांक व न्यायालय के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया है कि उनके पिता को उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन किस न्यायालय व न्यायाधीश / पीठासीन अधिकारी ने किस दिनांक को किया गया है। रेस्पों के पिता को वादग्रस्त भूमि का आवंटन नहीं हुआ है बल्कि रेस्पों के पिता कल्याण पुत्र जुबारया मीना ने जैक जुगाड के प्रभाव में लेकर राजस्व कर्मचारियों को लेकर या मिलकर के वादग्रस्त भूमि में स्वयं का नाम सीधे ही जमाबंदी में अंकित कराया है। जिसकी जानकारी अपीलांट को होते ही उसने सक्षम न्यायालय में न्याय प्राप्ति की आशा में वादी अपीलांट के हितों को अनदेखा करके निर्णय दिया जो विधि विरुद्ध है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 86/22 में दिनांक 7.7.23 को एक प्रार्थना पत्र पेश करवाया। जिसके अनुसार न्यायालय को मौका कमिश्नर की रिपोर्ट मंगवानी चाहिए थी। जिससे यह साफ साफ स्पष्ट हो जाता कि वादग्रस्त भूमि पर किसका कब्जा कब से चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

रेस्पो0 के प्रभाव में आकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सीपीसी का कोई महत्व नहीं दिया। जिसके तहत वादग्रस्त भूमि पर मौका कब्जा किसका है। इस बात की स्पष्ट लिखित जानकारी न्यायालय को प्राप्त होती जो वाद पत्र के निस्तारण का भी मुख्य भाग है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। मात्र रेस्पो0 ने अपने नाम की खसरा मिर्चदावरी व जमाबंदी के आधार पर यह दर्शाया है कि वादग्रस्त भूमि उनकी है। जबकि वास्तविकता में अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर अपने वुजुर्गान के समय से ही अर्थात् दुर्गा पुत्र साधुल्यो मीना व उसके पूर्वजों से कब्जा रिकार्डेड जमाबंदी में चला आ रहा है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 5 से भी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने से पहले वादग्रस्त भूमि की कब्जे संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट अपने अधिनस्थ कार्मिक या गठित टीम के द्वारा प्राप्त करनी चाहिए थी। जो प्राप्त नहीं की गई है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि हमारे पिता कल्याण ग्राम पूनेता के निवासी हैं तथा ग्राम पूनेता में उक्त भूमि पर काफी समय से काबिज काश्त होने के कारण पुराने कब्जे के आधार पर उक्त भूमि कल्याण को अलोट की गई थी जिस पर जब तक कल्याण जीवित था तब तक उनका तथा उनके बाद हम रेस्पो0 काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि से अपीलान्ट या उसके पूर्वजों के काश्त की रही थी तो उक्त भूमि हमारे पिता कल्याण को अलोट होते ही अपीलान्ट या उसके पूर्वजों द्वारा आवंटन को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जो अपीलान्ट व उसके पूर्वजों द्वारा आज तक नहीं की गई है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट का उक्त भूमि से कोई संबंध वास्ता नहीं है। उक्त भूमि रेस्पो0 के स्वामित्व एवं अधिकारी की भूमि है जो हमारे पिता कल्याण की खातेदारी में दर्ज है तथा कल्याण का स्वर्गवास हो जाने से उनकी विरासत का नामा0 रेस्पो0 के नाम खुलना है। जिसको रूकवाने की नियत से ही अपीलान्ट द्वारा मनगढन्त कहानी बनाकर अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओं का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलान्धीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। रेस्पो0 उक्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। किसी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की प्रक्रिया के तहत ही अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजीयात पर अपना कब्जा बताते हुए अप्रार्थीगण/रेस्पो0 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। परन्तु अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में विवादित भूमि पर कब्जा होने एवं किसी

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

प्रकार का राजस्व रिकार्ड उनके नाम होने के संबंध में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है ना ही अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में पेश किया है। जिससे की भूमि पर कब्जा एवं खातेदारी अपीलांट की सिद्ध हो सके। अपीलांट द्वारा केवल मात्र एडवर्स पजेशन के आधार पर रेस्पोंडेंट के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है। जबकि कानून में एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजीयात की खातेदारी कल्याण पुत्र जुबारया के नाम दर्ज रिकार्ड है जो रेस्पोंडेंट के पिता है। जो जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 से स्पष्ट है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दुओं प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की विवेचना किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के मु०न० 86/22 निर्णय दिनांक 23.12.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.6.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(लक्ष्मी कान्त बालोत)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर